सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-10 22 मई, 2015 पृष्ठों की संख्या 8 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, 2015 के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महारैली

दिल्ली : संसद मार्ग पर किसानों की महारैली को सम्बोधित करते हुए कामरेड सत्यवान

दिल्ली : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, 2015 के खिलाफ 5 मई को दिल्ली में संसद मार्ग पर अखिल भारतीय किसान महारैली हुई। ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस), नेशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूवमेन्ट (एनएपीएम), ऑल इण्डिया यूनियन ऑफ फोरेस्ट वर्किंग पीपल (एआईयूएफडब्ल्यूपी), ऑल इण्डिया किसान सभा(अजय भवन), ऑल इण्डिया किसान सभा (कॅनिंग लेन), लोक संघर्ष मोर्चा, जन संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन, किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान संघर्ष समिति, दिल्ली सोलिडेरिटी ग्रुप, किसान मंच सहित 40 संगठनों को लेकर गठित 'भूमि अधिकार आन्दोलन' के आह्वान पर हुई।

इस विरोध रैली में किसान-खेतमजदूरों के इन संगठनों के हजारों कार्यकर्ता-समर्थकों ने शिरकत की।

एआईकेकेएमएस के नेता और एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, 2015 के खिलाफ किसान आन्दोलन का एसयूसीआई(सी) पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ हमारा संगठन एआईकेकेएमएस क्षेत्रीय स्तर पर किसान-खेतमजदूरों को लामबंद कर रहा है।

रैली में सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी. राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक के डी. देवराजन, एसयूसीआई(सी) के कॉ. प्राण शर्मा और नेशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूवमेन्ट (एनएपीएम) की मेधा पाटकर ने भी अपनी बात रखी। सभी संगठनों द्वारा मोदी सरकार से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, 2015 रद्द करने की माँग की गयी।

बाल श्रम को पिछले दरवाजे से कानूनसम्मत बनाने की कुटिल चाल है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक का बीजेपी सरकार का फैसला

–एसयूसीआई(सी)

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 14 मई, 2015 को जारी एक बयान में कहा :

हर तरह के वाणिजिक उद्यमों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक का बीजेपी सरकार का ताजातरीन फैसला बाल श्रम को पिछले दरवाजे से कानूनी इजाजत देने की एक कुटिल चाल है। अलबत्ता शर्त यह है कि बच्चे खेतों में काम कर सकते हैं, पारिवारिक कारोबार में लग सकते हैं, विज्ञापनों, फिल्मों और टेलिविजन सीरियलों जैसे मनोरंजन उद्योग में काम कर सकते हैं और खेलकूद गतिविधियों में काम कर सकते हैं, वे ये सब काम स्कूल के बाद, गर्मियों की छुट्टियों में कर सकते हैं। यह श्रम के अनौपचारीकरण को ही बढ़ायेगा और पारिवारिक उद्यमों की परिभाषा के अन्दर माचिस बनाने, कालीन बुनने और हीरे तराशने के उद्योगों को शामिल करते हुए करार के आवश्यक भाग 'मनाही' को मजे से दरकिनार किया जा सकेगा और घरेलू कामों के साथ लड़कियों को बांधे रख कर उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा सकेगा।

हालांकि अब तक अधिकारिक तौर पर बाल श्रम की मनाही है, फिर भी तथ्यों को दबाने-छिपाने और चालाकी से हेराफेरी के जरिये अथोरिटियों की तरफ से इसके आकड़ों को कम करके दिखाने की भरसक कोशिशों के बावजूद बाल श्रम खतरनाक हद तक

(शेष पृष्ठ 2 पर)

द्वितीय विश्वयुद्ध में फासीवादी शक्तियों पर सोवियत रूस की लाल सेना की विजय की 70वीं सालगिरह पर सभा

पटना (बिहार) : द्वितीय विश्वयुद्ध में फासीवादी शक्तियों पर सोवियत रूस की लाल सेना की विजय के 70वें साल के मौके पर 11 मई को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में स्थानीय आईएमए हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरूण कुमार सिंह ने कहा कि जर्मन एकाधिकारी पूंजी की मदद से हिटलर ने जब जर्मनी में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, तब पश्चिमी साम्राज्यवादी देश अमेरिका-ब्रिटेन-फ्रांस चाहते थे कि हिटलर युद्ध की ताकत को बढ़ाकर सोवियत संघ पर हमला कर दुनिया के पहले समाजवादी देश मजदूर वर्ग के राज्य को बर्बाद कर दे। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी सीमा पर दूसरा मोर्चा खोलने के सवाल पर अमेरिकी-ब्रिटिश शासक शुरू से ही टालमटोल करते रहे। फासिस्ट सेना जब अपने तेज हमलों के साथ सोवियत संघ (रूस) में बड़े पैमाने पर हत्याओं और बर्बादियों का दौर चला रही थी, तब स्तालिन ने अमेरिकी-फ्रांसीसी-ब्रिटिश शासकों से बार-बार अनुरोध किया कि वे फ्रांस की ओर से जर्मनी के खिलाफ हमले शुरू करें। अगर ऐसा होता तो हिटलर पूर्वी रणक्षेत्र से अपनी सेना को हटाकर पश्चिमी रणक्षेत्र में ले जाने को मजबूर होता और इस प्रकार सोवियत रूस के खिलाफ हमले में कुछ कमी आती। लेकिन पश्चिमी साम्राज्यवादी शासकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अत: सोवियत संघ को जर्मनी के खिलाफ अकेले ही लड़ना पड़ा। उन्होंने चुनावी फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश में फासीवाद-सम्प्रदायवाद के बढ़ते खतरे व सरकार मजदूर-किसान विरोधी, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन निर्मित करने की जरूरत पर बल दिया।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पटना : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड अरूण कुमार सिंह

किसानों की बरबाद फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

इलाहाबाद(उ.प्र.) : 27 मई को पार्टी की एस.यू.सी.आई.(सी) की इलाहाबाद इकाई ने प्रदेश के किसानों की असमय बारिश से बरबाद फसलों के उचित मुआवजे के अविलम्ब भुगतान की माँग को ले कर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की भी माँग की गयी। सभा के मुख्य वक्ता कॉ. कमलेश सिंह ने किसानों की बदहाली और उपेक्षा पर विक्षोभ व्यक्त करते हुए कहा

इलाहाबाद में प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

कि आज किसान निराशा-हताशा के दुश्चक्र में घिरा हुआ आत्महत्या के लिये विवश हो रहा है या सदमे से मौत का शिकार हो रहा है। इस स्थिति से निकलने के लिये एक संगठित जन आन्दोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

सभा का संचालन कॉ. विनोद यादव ने किया। सभा में कॉ. एस.के. मालवीय, सुमन लता शुक्ला, झरना मालवीय, नन्द लाल गुप्ता, आशू ठाकुर, विजय शंकर, अंकुश दुबे, रश्मि मालवीय आदि ने भी भाग लिया।

ऊदपुर गेल्हवा गाँव के किसान-मजदूर आन्दोलन की राह पर

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.): गौरतलब है कि वर्षों पहले जौनपुर जिला के बदलापुर तहसील के अन्तर्गत स्थित ऊदपुर गेल्हवा गाँव में चकबंदी के दौरान हुई धांधली व भ्रष्टाचार से किसानों को भारी नुकसान पहुँचाया गया, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई। इस बात को लेकर ऐसे सैकड़ों पीड़ित किसानों और महिलाओं ने अपनी आवाज बुलन्द कर प्रशासन के कानों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए दर्जनों बार तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप प्रदेश के चकबंदी आयुक्त ने

पीड़ित किसानों की आवाज को संजीदगी से लेते हुए गाँव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कर पुन: चकबंदी कराने का फरमान जारी किया। लेकिन चकबंदी प्रक्रिया में लाभ प्राप्त किए मालदार पक्षकारों ने पुन: चकबंदी कराने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुँच कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उधर पीड़ित किसानों ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश निरस्त कराने में कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह आज तक प्रदेश चकबंदी आयुक्त के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है बल्कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गाँव में पक्की सड़क का निर्माण कर चकों की नवैयत में परिवर्तन किया जा रहा है। यह बात पीड़ित किसानों को नागवार लगी और उन सब ने लामबन्द होकर विरोध किया। सड़क निर्माण के लिए आ रही गिट्टी लदी ट्रक को रोक कर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जिलाधिकारी, जौनपुर ने बदलापुर की एस.डी.एम. के साथ पी.एस.सी. के जवान, कई थानों की फोर्स व सी.ओ. को भेजकर जबरन सड़क निर्माण कराना चालू कर दिया। पुलिस फोर्स छावनी में तब्दील ऊदपुर गेल्हवा गाँव के किसानों को डराया-धमकाया जा रहा है। बावजूद इसके किसानों व महिलाओं ने सड़क को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया और पुलिस-प्रशासन व किसानों की संख्या आमने-सामने संघर्ष करने के लिए आ गई। इस तरह हर दिन संघर्ष गहराता जा रहा है। गाँव वालों पर पुलिसिया रौब, खाकी वर्दी का तांडव, मारपीट, गिरफ्तारी, झूठे मुकदमें लादे गये है और कई किसानों को जेल में डाल दिया गया है। डी.एम., एस.डी.एम. व पुलिस प्रशासन की इस दादागिरी के खिलाफ एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) ने 16 अप्रैल को सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों के साथ बदलापुर तहसील परिसर में रैली एवं प्रदर्शन का आयोजन कर उपजिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री उ.प्र. को ज्ञापन सौंपा और तुरन्त हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की। सभा को कॉ. दिनेश कान्त दूबे, प्रमोद कुमार शुक्ला, झरना मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, कृष्णा सिंह, रविशंकर मौर्य, इन्दु कुमार शुक्ल इत्यादि ने सम्बोधित किया। आन्दोलन अभी जारी है।

बाल श्रम ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यह दमनकारी पूंजीवाद ही है जो बाल श्रम के अभिशाप को पनपाता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता है। बेरहम पूंजीवाद द्वारा लगातार कंगाल बनाये गये मां-बाप अपने छोटे-छोटे बच्चों को श्रम बाजार में धकेल देते हैं क्योंकि वे अपनी औलाद का पेट नहीं भर सकते। बाल श्रम के नियोक्ता मालिक भी इसे बेहद फायदेमंद पाते हैं क्योंकि उन्हें छोटे बच्चे या तो मुफ्त में या निहायत ही कम दिहाड़ी पर काम करने को मिल जाते हैं और वे शोषण की दुकानों में घोर अस्वास्थ्यकर हालात में दिन में 8 घण्टे से ज्यादा घण्टों तक काम लिये जाने पर ऐतराज भी नहीं करते हैं। ज्यादातर मामलों में, ये बच्चे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। पूंजीवादी भारत में बच्चों का यह क्रूर और खौफनाक शोषण सरकार व प्रशासन की नाक के नीचे होता है जो या तो मूक दर्शक या तमाशाई बना हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है या कभी-कभी तो इस अपराध को सरअंजाम देने में छिपे तौर पर सहअपराधी होता है।

धूर्तता और बेईमानी यह है कि बीजेपी सरकार ने शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों के स्वार्थ साधते हुए देश के सामाजिक ताने-बाने और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की दुहाई देते हुए चुनिंदा कुछ क्षेत्रों में बाल श्रम की छूट देने के अपने फैसले को जायज ठहराना चाहा है। लेकिन इसने जिस सच्चाई पर पर्दा डाला है वह यह है कि बाल श्रम पनपाने के अलावा, इस दमनकारी अमानवीय पूंजीवाद के द्वारा इसे और भी पुख्ता किया जा रहा है और जारी रखा जा रहा है। चाहे कितने ही कानून बना लो, बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि इस सड़े-गले भ्रष्ट पूंजीवाद को उखाड़ फेंक नहीं दिया जाता।

हालांकि, बाल श्रम क्योंकि मां-बाप और परिवारों की खस्ताहाल होती जा रही माली हालत की अनिश्चित घटना पर निर्भर है, इसलिए इसकी बढ़ोतरी की कुछ हद तक रोकथाम की जा सकती है अगर ईमानदार बाल अधिकार कार्यकर्ताओं सहित लोकतांत्रिक ख्यालात वाले सभी विवेकशील लोग माली हालत खस्ता होने की घोर मजबूरी में बच्चों को काम पर भेजने वाले गरीब और लुटे-पिटे परिवारों की माली हालत की बेहतरी की माँग सहित जनजीवन की ज्वलंत माँगों पर आधारित जोरदार जनवादी आन्दोलन खड़ा करने में मेहनतकश जनता के बाकी तमाम तबकों से हाथ मिला लें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसा आन्दोलन पूंजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलन के परिपूरक के रूप में गठित हो।

द्वितीय विश्वयुद्ध में फासीवादी शक्तियों पर ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. स्वप्न चटर्जी ने जर्मनी में फासीवाद के उभार पर चर्चा करते हुए कहा कि द्वितीय विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी युद्ध ही था। उभरते हुए साम्राज्यवादी देश जर्मनी को तब दुनिया का बाजार चाहिए था। शोषण के लिए उसे नये उपनिवेशों की जरूरत थी, लेकिन दुनिया तब अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रांसीसी व अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादियों के बीच आपस में बंट चुकी थी। युद्ध के बगैर इस कब्जेदारी में बदलाव होने वाला नहीं था, इसलिए जर्मनी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फासीवाद में बड़े पैमाने पर अंधता, अतार्किकता और गैर-वैज्ञानिक मानसिकता को फैलाया जाता है, मानवीय नाते-रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं।

सभा को सम्बोधित करते हुए एनआईटी, पटना के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रो. संतोष कुमार ने कहा कि दुनिया की 80 प्रतिशत जनता को समझाया गया है कि अमेरिका-ब्रिटेन-फ्रांस के चलते ही नाजी ताकतों की हार हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि फासीवादी ताकतों को समाजवादी सोवियत संघ ने ही शिकस्त दी। फासीवाद के खिलाफ तमाम शक्तियों को एकजुट होने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पत्थर जो फासिस्टों के खिलाफ फेंका जा रहा हो, उसका स्वागत होना चाहिए।

वहीं मशहूर गणितज्ञ विकास राही ने फासीवाद और हिटलर को परास्त करने वाले महान नायक स्तालिन के चरित्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आज फासीवाद के खिलाफ तमाम वामपंथी शक्तियों को एकजुट होना चाहिए। इसमें छोटे-छोटे वैचारिक मतभेद बाधक नहीं बनने चाहिए।

सभा की अध्यक्षता करते हुए एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी के सचिव कॉ. शिव शंकर ने कहा कि सोवियत समाजवाद के ध्वस्त होने से न केवल रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में अंधेरा छा गया, बल्कि पूरी दुनिया को ही पूंजीवादियों-साम्राज्यवादियों के बेरोकटोक लूट का क्षेत्र बना दिया गया। आज साम्राज्यवादियों ने बेरोकटोक पूरी दुनिया पर युद्ध थोप दिया है। यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका-हर जगह आज युद्ध में हजारों हजार बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ रोटी-कपड़ा-मकान की समस्या ही नहीं, बल्कि युद्ध से मानव मुक्ति की राह भी समाजवाद में ही है। सभा का संचालन एसयूसीआई (सी) पटना जिला सचिव कॉ. साधना मिश्रा ने किया। सभा का समापन अंतर्राष्ट्रीय गीत से हुआ।

पेट्रोल-डीजल मूल्यवृद्धि का विरोध

पुतला दहन करते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.) : बीजेपी सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाने का एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) कार्यकर्ताओं ने 17 मई को कड़ा विरोध किया और इस वृद्धि को तत्काल रद्द करने की मांग की। बदलापुर के इन्दिरा चौक पर केन्द्र सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर कॉ. रविशंकर मौर्य, हीरालाल गुप्त, राजबहादुर, लालता प्रसाद, जयराम, दिनेश, मिथिलेश, दिलीप, कमलेश, इन्दुकुमार शुक्ल आदि उपस्थित थे।

हमें जनता के बीच रहकर, उनके सुख-दुख में शामिल होकर उनके अंदर परिवर्तन लाना होगा

—कॉमरेड रंजीत धर

पटना में सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड रंजीत धर

पटना : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी स्थापना दिवस पर पटना में हुई सभा में मुख्य वक्ता थे पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर। सभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिव कॉ शिवशंकर ने की। कॉ रंजीत धर ने कहा :

कॉमरेड अध्यक्ष और कॉमरेड,

आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा स्थापित हमारी प्रिय पार्टी, भारत के सर्वहारा वर्ग की पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का स्थापना दिवस है। इसी मौके पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ यह विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज की स्थिति क्या है? और उस स्थिति में एक क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य के तौर पर हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या करना है? इसको विचारना, जाँचना तथा आने वाले दिनों में हम कैसे चलेंगे–इन बातों का हमें निर्धारण करना है। मुख्य तौर पर हमें समझना चाहिए कि देश की जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? आप लोग जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ, एक के बाद एक सरकारें आयीं, सरकारों में परिवर्तन हुआ–चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। किसी एक पार्टी का शासन नहीं रहा। कांग्रेस, भाजपा की सरकार आयी, वी पी सिंह की सरकार आयी, राजीव गाँधी की सरकार आयी, वाजपेयी की सरकार आयी। अभी नरेन्द्र मोदी की सरकार चल रही है। सभी नेता चुनाव से पहले अच्छी-अच्छी बाते करते हैं। लेकिन उनके सरकारी सत्ता में जाने के बाद जनजीवन में, मजदूर-किसान, मध्यम वर्ग के जीवन में लगातार गिरावट आ रही है। दिन पर दिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यानी सरकारों का परिवर्तन हो रहा है, जन-जीवन में उतना ही संकट बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार अगर है भी तो वह ठेके पर। स्थायी नौकरी नहीं है। एक पर एक उद्योग बंद हो रहे हैं। चारों तरफ संकट छाया हुआ है। गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। संकट बढ़ रहा है। आम आदमी का जीवन संकट से और बड़े संकट में घिरता जा रहा है। कारण क्या है? हमें इस पर विचार करना चाहिए।

दुनिया में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। जब कोई आदमी हंसता है, तो उसकी हंसी के पीछे भी कोई कारण होता है। जब कोई आदमी रोता है, तो उसके रोने के पीछे भी कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई हंसता भी नहीं है, कोई रोता भी नहीं है। यदि कोई आदमी बिना कारण के हंसता है, रोता है, तो लोग कहते हैं उसका दिमाग खराब हो गया है। वह स्वस्थ नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण है।

चुनाव के जरिये मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार बनती है। वे जनता से लम्बे-चौड़े वायदे कर सरकार में जाते हैं और सरकार में जाने के बाद आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती है। उनकी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। इसका कारण क्या है? इस कारण को यदि न ढूंढ़ा जाय, यदि कारण को दूर न किया जाय, तो हम जो भी कोशिश क्यों न करें, हम जितना भी चाहें, जो स्थिति बनी हुई है, वह चलती रहेगी। उसमें आप परिवर्तन नहीं ला पायेंगे।

आप लोगों को समझना होगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश को अंग्रेज उपनिवेश बनाकर लूट रहे थे। आजादी आंदोलन हुआ। आजादी आंदोलन के जरिये हमें आजादी मिली। अंग्रेज बाहर से आकर हमारे देश की प्राकृतिक सम्पदा और सस्ते मजदूरों का शोषण कर, मुनाफा कमा कर अपने देश ले जाते थे। भारत उनका उपनिवेश था। उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था। यहाँ अपना शासन स्थापित किया था और इस प्रकार वे यहाँ की प्राकृतिक सम्पदा को लूटा करते थे। हवा, पानी, हमारे देश में धरती के नीचे खान-खदानों में जो कुछ था, वे सब कुछ लूटते थे। करोड़ो रुपये कमाकर वे अपने देश में ले जाते थे। इस तरह से वे हमारे देश का शोषण करते थे। हमने आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें आजादी मिली। लेकिन हुआ क्या?

एक मशीन के सहारे अंग्रेज हमारे देश पर शोषण करते थे, मुनाफा कमाते थे, लूटते थे। उन्होंने ऐसा कैसे किया? लूटने के लिए उन्होंने अपना कानून बनाया था, अपनी पुलिस-मिलिट्री तैयार की थी, अपनी न्यायपालिका तैयार की थी। उन्होंने अपने यातायात के साधन तैयार किये थे। इस मशीन को मानकर चलना होता था। इन चीजों को लोग मानते हैं या नहीं–इसे देखने के लिए उन्होंने न्यायपालिका तैयार की थी, कोर्ट-कचहरी तैयार की थी। मतलब एक राजसत्ता कायम की। बात ऐसी नहीं थी कि अंग्रेज यहाँ आये और फिर यहाँ से चले गये। उन्होंने एक प्रणाली लागू की, एक राजसत्ता तैयार की। राजसत्ता का मतलब पुलिस-मिलिट्री, न्यायपालिका और प्रशासन है। इस राजसत्ता के जरिये वे हमारे देश को लूटते थे।

हमारे देश की स्थिति को आपको गहराई से समझना होगा। भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश की हालत क्या है? आज भाजपा है, कल वह चली जा सकती है। उसकी जगह पर फिर कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, फिर कोई तीसरी पार्टी आ सकती है। लेकिन आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुनाव के जरिये सरकारों के परिवर्तन द्वारा आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आयेगा। चुनाव से सिर्फ सरकारें बदलती हैं। जो कानून बने हुए हैं, जो न्यायपालिका बनी हुई है, जो पुलिस-मिलिट्री है, उनमें चुनाव नहीं होता है। चुनाव पार्टियों में होता है। चुनाव मिलिट्री में नहीं होता है, पुलिस में नहीं होता है। हाई कोर्ट के जजों का चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है सांसदों का। चुनाव के जरिये परिवर्तन होता है सरकार का, मतलब ड्राइवर का, ऑपरेटर का। बदलते हैं मशीन चलाने वाला, यानी ऑपरेटर। लेकिन मशीन नहीं बदलती है।

देश की आजादी की लड़ाई में टाटा-बिड़ला आये थे और देश के आम किसान-मजदूर, मध्यमवर्गीय लोग व शोषित अवाम भी आये थे। इन दोनों का लक्ष्य एक नहीं था। आजादी आंदोलन में पूंजीपति वर्ग ने मदद की। लेकिन कुर्बानी दी भगत सिंह, खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद जैसे हजारों हजार गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों के लड़कों ने। पूंजीपति वर्ग ने पैसा देकर आजादी आंदोलन में मदद की। उन्होंने ऐसा क्यों किया?

हमारा समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है। हमें अपने देश को पहचानना होगा। हमें सत्य को ढूंढ़ना चाहिए। अगर आप सत्य न ढूंढ़ सकें, तो आप गलत रास्ते पर चलेंगे। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको सोचना चाहिए कि किस कारण से, किस नियम से यह सब हो रहा है। उन अंग्रेजों ने देश को लूटने के लिए जो मशीन लगाई थी, जो पुलिस-मिलिट्री-कानून बनाया था, उनके चले जाने के बाद हमारे देश के टाटा-बिड़ला उस मशीन के मालिक बन बैठे हैं। शोषण-लूट की मशीन ही रह गयी। जो लूट अंग्रेज किया करते थे, वही लूट आज देश में टाटा-बिड़ला-अंबानी आदि पूंजीपति कर रहे हैं। आजादी आम आदमी को नहीं मिली। किसान-मजदूरों को शोषण-लूट से मुक्ति नहीं मिली।

राजसत्ता और सरकार दोनों अलग-अलग चीजें हैं। राज्य स्थायी है, मगर सरकार बदलती रहती है। चुनाव के जरिये सरकार बदलती है, लेकिन राजसत्ता में बदलाव नहीं होता है। मोटर गाड़ी का ईंजन नहीं बदलता है, सिर्फ उसका ड्राईवर बदलता है। ईंजन वही रह गया। ऑपरेटर बदलने से मशीन से दूसरा कुछ उत्पादन नहीं होगा, वही होगा जो पहले वाले ऑपरेटर के जरिये होता था। गन्ना पेरने वाली मशीन से गन्ने का रस निकलता है, उसमें से कागज नहीं निकलेगा। यदि आप कपड़ा तैयार करना चाहते हैं, तो आपको कपड़ा तैयार करने वाली मशीन लगानी होगी। अगर आप स्टील बनाना चाहते हैं, तो आपको स्टील तैयार करने वाली मशीन लगानी होगी। अलग-अलग मशीन से अलग-अलग चीजें तैयार होती हैं। एक ही मशीन से सारी चीजें तैयार नहीं होती हैं। राजसत्ता भी मशीन की ही तरह है। जिस मशीन के जरिये वे लूटते थे, वह मशीन आज भी है। अंग्रेज चले गये। लेकिन लूटने की व्यवस्था बनी हुई है। आज कौन लूट रहा है? लूट रहा है पूंजीपति वर्ग। टाटा-बिड़ला मालिक बन गये। राजसत्ता ही मूल कारण है, जिसके जरिये शोषण चल रहा है। ये जो बेरोजगारी है, ये तमाम समस्याएं जो आप देख रहे हैं, सब कुछ राजसत्ता के कारण है। अगर राजसत्ता को बदला न जाय, तो सिर्फ सरकार बदलने से मुक्ति नहीं मिलेगी।

यह सही है कि चुनाव में हम भाग लेते हैं। हम चुनाव में इसलिए जाते हैं कि यदि चुनाव में सर्वहारा वर्ग की पार्टी विजयी होती है, तो इसके जरिये वह जन आंदोलन को तेज कर सकेगी। हमें जन आंदोलन को तेज करना चाहिए। यह जो राजसत्ता है, जिसके जरिये देश में शोषण चल रहा है, उसे कैसे बदला जायेगा? इस राजसत्ता को बदलकर जनता के विकास के अनुरूप एक राजसत्ता की स्थापना करनी है। यह काम क्रांति के जरिये ही हो सकता है। इसके लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी जन आंदोलन के जरिये करनी होगी। जन आंदोलन को धीरे-धीरे तेज करते हुए जनता को क्रांति के लिए सचेत करना होगा। उसे जन आंदोलन के जरिये राजसत्ता के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देनी होगी। लड़ाई जितनी तेज होगी, उसके जरिये वे लड़ाई के तरीके को समझेंगे, लड़ाई के कायदे को समझेंगे। यह काम सिर्फ भाषण से नहीं होगा। वास्तव में आंदोलन खड़ा करना होगा। आंदोलन में जनता को शामिल करना होगा। आंदोलन के द्वारा राजसत्ता के खिलाफ लड़ना होगा। लड़ते हुए धीरे-धीरे जनता को क्रांति के बारे में सचेत और संगठन को मजबूत करना होगा। नहीं तो देश में जो चल रहा है, वही चलता रहेगा।

भाजपा के आने के बाद स्थिति क्या हो गयी है? भाजपा कैसे आ गयी? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 10 साल तक सत्ता में रही। सत्ता में कोई भी आ जाये, वह इस पूंजीवादी व्यवस्था में मशीन के ड्राईवर के रूप में ही काम करेगा। वह शोषण को ही जारी रखेगा। शोषण की नीति को ही आगे बढ़ायेगा। तो मनमोहन सिंह हों या राजीव गांधी या इंदिरा गांधी–जो भी क्यों न हो, सभी ने इसी नीति को आगे बढ़ाया।

देश आजादी आंदोलन के दौरान वर्ग विभाजित था। आज भी देश वर्ग विभाजित है। अमीर और गरीब इन दोनों वर्गों में समाज विभाजित है। दोनों वर्गों के स्वार्थ अलग-अलग हैं। दोनों वर्गों का उद्देश्य, दोनों वर्गों का स्वार्थ कभी एक नहीं हो सकता। मालिक और मजदूर दोनों अपने-अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं। मालिक मजदूरों को ठगते हैं, जबकि मजदूर मालिकों की ठगी से मुक्ति चाहते हैं। मजदूर और मालिक का लक्ष्य कभी एक नहीं हो सकता। मालिक का लक्ष्य है लूटना, मुनाफा कमाना और मजदूर का लक्ष्य है शोषण से मुक्ति हासिल करना।

हमें देश को समझने की जरूरत है। देश क्या है? देश कौन चलाता है? अंग्रेज शासन और शोषण करते थे। वे मशीन के मालिक बन बैठे थे। अब अपने देश के पूंजीपति मालिक बन गये हैं। मजदूर मजदूर ही रह गया है। गरीब गरीब ही रह गया, उसे मुक्ति नहीं मिली। जब तक वे राजसत्ता को अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, तब तक सरकार में जितना भी बदलाव क्यों न लाया जाय, परिवर्तन नहीं हो सकता। समाज सहित सब कुछ वैज्ञानिक नियम से संचालित

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कॉ. रंजीत धर का भाषण..

(पृष्ठ 3 का शेष)

होता है। नियम से बाहर कुछ भी नहीं है।

कॉमरेड शिवदास घोष ने आजादी के बाद 1948 में एसयूसीआई (सी) की स्थापना की। उन्होंने इसकी स्थापना क्यों की? उस समय तो मजदूर वर्ग की पार्टी के नाम पर कई पार्टियां थी, कम्युनिस्ट नामवाली पार्टी भी थी। पहले तो एक ही कम्युनिस्ट नामवाली पार्टी थी, जबकि आज तो कम्युनिस्ट नाम से कई पार्टियां हैं। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी काफी ताकतवर थी। उस समय देश के जाने-माने बुद्धिजीवी, शिक्षित लोग सीपीआई में थे। उसका जनाधार भी बहुत था। मजदूर आंदोलनों में उन्होंने नेतृत्व भी दिया था। फिर भी कॉमरेड शिवदास घोष ने एसयूसीआई (सी) का निर्माण क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि बिना पार्टी के मजदूर वर्ग को मुक्ति नहीं मिलेगी।

वर्ग विभाजित समाज में पार्टी किसी न किसी वर्ग की पार्टी होती है। वर्ग विभाजित समाज में वर्ग की जो इच्छा है, आकांक्षा है, चाहत है, उसे वर्ग कैसे पूरा करेगा? गरीब लोग, किसान-मजदूर अलग-अलग हैं, उनमें पूरी तरह से एकता नहीं है। अगर उन्हें इस राजसत्ता के खिलाफ लड़ना है, अगर उन्हें अपनी मुक्ति हासिल करनी है, तो उन्हें अपनी पार्टी चाहिए। बिना पार्टी के शोषित वर्ग को एक मंच पर नहीं लाया जा सकता। बिना पार्टी के उनके संघर्षों का संचालन कैसे होगा? बिना पार्टी के वर्ग की मुक्ति नहीं होगी। गरीब किसान-मजदूरों का कर्तव्य है कि वे पूरी ताकत लगाकर अपने वर्ग की पार्टी को ताकतवर बनायें। क्योंकि, पार्टी के जरिये ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है। हमारे देश में पूंजीपति वर्ग के स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो पार्टी है, वह है कांग्रेस। कांग्रेस को टाटा भी मदद करता था, बिड़ला भी मदद करता था। पूंजीपति वर्ग भी मदद करता था। गांधीजी जब जाते थे, बिड़ला के घर में रहते थे। पूंजीपति वर्ग ने पैसे से कांग्रेस को मदद की। पूंजीपति वर्ग चाहता था कि कांग्रेस के जरिये यदि आजादी मिलती है, तो जो राजसत्ता हमारे हाथ में आयेगी, उस पर टाटा-बिड़ला आदि पूंजीपति मालिक बन बैठेंगे। टाटा-बिड़ला यही चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज जो धन लूटकर विदेश ले जा रहे हैं, उनके चले जाने के बाद हम यहाँ के मालिक बन जायें। देश की तमाम प्राकृतिक सम्पदा को हम लूटें। आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आयी। सत्ता में आने के बाद पूंजीपति वर्ग, टाटा-बिड़ला की जो सम्पत्ति थी, उसमें काफी इजाफा हुआ। कहा जाता है कि भारत गरीब देश है। दरअसल यहाँ की आम जनता गरीब है। लेकिन यहाँ के मुट्ठीभर पूंजीपति गरीब नहीं हैं। उनकी तो पूंजी की कोई सीमा-परिसीमा नहीं है। यह पूंजी कहाँ से आयी? क्या हर पूंजीपति के घर में नोट छापने की मशीन है? आजादी के बाद हमारे देश में जो शासन कायम हुआ, वह पूंजीपति वर्ग का शासन था। भारतीय पूंजीपति सत्ता में आने के बाद मुनाफा लूटने लगे। कितना मुनाफा कमाया? आज भारत के पूंजीपति दुनिया के विभिन्न देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब व अफ्रीका में जाकर अपनी पूंजी निवेश कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। इतनी पूंजी है इनके पास! दुनिया के सबसे बड़े 10 पूंजीपतियों में 5 भारत के हैं।

और हमारी पार्लियामेंट? जिस पार्लियामेंट का अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ। जो पार्लियामेंट देश का संचालन करती है, उस पार्लियामेंट में करीब साढ़े पांच सौ सदस्य हैं। इनमें 300 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। ज्यादातर सांसद करोड़पति हैं। इस स्थिति में गरीबों की क्या हालत होगी? उनकी हालत और बदतर होगी।

हमारे देश में सीपीआई, जो कि अपने को मजदूर वर्ग की पार्टी होने का दावा करती है, वह सर्वहारा वर्ग की पार्टी के तौर पर निर्मित नहीं हो सकी। इस विषय को आपको गहराई से समझना होगा। क्यों इतनी लड़ाइयों के बाद भी हमारे देश में जनता को मुक्ति नहीं मिली? आजादी के बाद कोई कम लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गयीं। मजदूरों-किसानों ने कोई कम संघर्ष नहीं किया। पूरे देश में अनेक बार हड़तालें हुईं। जेपी आंदोलन में बिहार में काफी लोग मैदान में उतरे। इस आंदोलन में बहुत सारे गरीब किसान-मजदूरों व नौजवानों ने भाग लिया। 1974 में विशाल आंदोलन हुआ। आजादी के पहले देश में जितने संघर्ष हुए, आजादी के बाद उससे ज्यादा संघर्ष हुए। इतने संघर्षों के बाद भी हम क्यों पिछड़ गये? इसका कारण ढूंढ़ना होगा। हमने संघर्ष किया, खून बहाया, कुर्बानी दी। जैसे कहा, वैसे ही लड़े। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेता सही नहीं थे, पार्टी सही नहीं थी। अगर सही मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं रहेगी, तो मुक्ति नहीं मिल सकती। बगैर अपनी पार्टी के वर्ग अपनी मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। वर्ग के हाथों में पार्टी अपना लक्ष्य पूरा करने का औजार है, जिसके बिना मजदूरों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। पूंजीपति वर्ग शोषण के लिए अपनी पार्टी तैयार करता है, उस पार्टी के निर्माण का तरीका, निर्माण की प्रक्रिया एक तरह की है। फिर मजदूर वर्ग शोषण से मुक्ति के लिए अपनी पार्टी का निर्माण करता है, उस पार्टी के निर्माण का तरीका, निर्माण की प्रक्रिया दूसरी तरह की है। दोनों के निर्माण का तरीका अलग-अलग है, दोनों के निर्माण की प्रक्रिया अलग-अलग है।

मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए जिस किस्म की पार्टी चाहिए, वह पार्टी जिस तरह के संघर्ष से बन सकती है, वह संघर्ष तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेकर चलने पर भी वह सही मायने में सर्वहारा वर्ग की पार्टी नहीं बन पायी। आज इतने सालों बाद यह बात साबित हो गयी है। कहाँ है सीपीआई-सीपीआई (एम)? सीपीआई (एम) नीचे गिरते-गिरते संसद में उसके मात्र 8-10 सांसद रह गये हैं। वह बंगाल से चली गयी, केरल से चली गयी। सिर्फ त्रिपुरा में रह गयी है। एक समय बिहार में सीपीआई की बहुत अच्छी स्थिति थी। 10-10 सांसद थे। आज कहाँ है बिहार में सीपीआई? जरूरत है सही मजदूर वर्ग की पार्टी की। उनकी पार्टी सही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए उन्होंने सही ढंग से संघर्ष नहीं किया। बिहार में हमारी पार्टी बहुत पुरानी है। जब बंगाल में पार्टी का निर्माण हुआ, लगभग उसी समय, एक-दो साल के अंदर बिहार में भी पार्टी का निर्माण हुआ। कॉमरेड प्रीतीश चंदा, कॉमरेड हिरेन सरकार के माध्यम से यहाँ पार्टी का काम-काज शुरू हुआ। हमारे सामने कॉमरेड शिवदास घोष की सीख है। क्रांति के बारे में हम जानते हैं। बावजूद इसके यहाँ जितना संगठन होना चाहिए, पार्टी जितनी ताकतवर होनी चाहिए, उतनी नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ढूंढ़ना होगा।

हमारी नीति-सिद्धांत सही है। नहीं तो आज पूरे देश में कहाँ है सीपीआई, कहाँ है सीपीआई (एम)? धीरे-धीरे ये पार्टियां पिछड़ रही हैं। जबकि एसयूसीआई (सी), कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन का पूरे हिन्दुस्तान में विस्तार हो रहा है। लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अनेक नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। संगठन तैयार हो रहा है। लेकिन भारत की क्रांति के लिए जितनी ताकत हुए बिना हम क्रांति नहीं कर सकते, राजसत्ता के खिलाफ नहीं लड़ सकते, उतनी ताकत हम आज तक हासिल नहीं कर पाये हैं। बाकी सारी स्थितियाँ क्रांति के पक्ष में हैं। पार्टी जब तक उतनी ताकत हासिल नहीं कर लेती, तब तक हम चाहने से भी क्रांति नहीं कर सकते। आज भी जो हमारी स्थिति है, जो हमारी ताकत है, यदि हम गंभीर हैं, यदि हम क्रांति को समझते हैं, देश को समझते हैं, यदि हम समझते हैं कि इस वजह से देश में शोषण हो रहा है, यदि समझते हैं कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो हम स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी यह समझ विज्ञान आधारित, तर्क आधारित और नियम आधारित है। इसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है।

आजादी तो मिली, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। देश के पूंजीपतियों ने आजादी का पूरा फल हड़प लिया। हमारी पार्टी शोषित वर्ग की पार्टी है। जब तक यह क्रांति लायक ताकत हासिल नहीं कर पायेगी, तब तक क्रांति संभव नहीं है। पूंजीवाद रहेगा। इसका मायने है कि आर्थिक संकट बढ़ेगा। मध्यमवर्गीय व्यक्ति धीरे-धीरे मजदूर, गरीब किसान बनता जा रहा है। आज देश की हालत क्या है? किसान रोजाना आत्महत्याएं कर रहे हैं। उद्योगों में मजदूरों की छंटनी हो रही है। नये उद्योग नहीं लग रहे हैं। नयी नियुक्ति नहीं हो रही है। जो रोजगार मिल रहा है, वह भी छीन रहा है। कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। आंदोलन के माध्यम से मजदूरों को जो अधिकार मिले थे, वे सब छीने जा रहे हैं। किसान अपना खून-पसीना बहाकर जो फसल तैयार कर रहे हैं, उसका सही मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार किस लिए है? यदि गरीब किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य न मिले, तो सरकार क्यों है? दरअसल सरकार मजदूर-किसानों की नहीं है। मजदूर-किसानों की जो चाहत है, उसे पूरा करने के लिए अपनी सरकार चाहिए, अपनी पार्टी चाहिए। इसलिए राजसत्ता का परिवर्तन चाहिए। यह काम सर्वहारा वर्ग को करना है।

इस सभा में अनेक पुराने साथी भी उपस्थित हैं। साथ ही अनेक नये लोग भी उपस्थित हैं। क्रांति के लिए एक नयी संस्कृति चाहिए। हम नया समाज बनाना चाहते हैं। नये समाज में नयी रीति होगी, नये नियम होंगे। जीवन के नये आदर्श होंगे। पुराने समाज की मानसिकता को लेकर यदि आप नये समाज में जायेंगे, तो नया समाज नहीं बनेगा। नये समाज के लिए नया चरित्र चाहिए, नयी संस्कृति चाहिए, नया जीवन चाहिए, नयी मानसिकता चाहिए। यह शोषण पर आधारित समाज है। हम इसे बदल कर शोषणविहीन एक नया समाज बनाना चाहते हैं। यदि संस्कृति में परिवर्तन न लाया जाय, यदि आदमी पुरानी संस्कृति को लेकर ही चलता रहे, तो नया समाज नहीं बन पायेगा। संस्कृति मूल है। संस्कृति मतलब आपका चरित्र, आपकी चाहत, आपके रिश्ते, आपकी इच्छाएं-सब कुछ संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। तो नये समाज के लिए नयी संस्कृति चाहिए और नयी संस्कृति के आधार पर नयी पार्टी चाहिए, जो पार्टी क्रांति कर सकती है। यदि चरित्र न रहे, संस्कृति न रहे और संस्कृति के आधार पर यदि आप संगठन न बना सकें, तो सोवियत संघ की तरह गिरावट आयेगी।

लेनिन-स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने जो क्रांति की, वह काफी दूर तक आगे बढ़ चुकी थी। माओ त्से-तुंग ने चीन में समाजवाद कायम किया, क्रांति की थी। लोग पूछ रहे हैं कि यदि कम्युनिज्म सही है, तो चीन में, रूस में समाजवाद क्यों खत्म हो गया? इसका कारण है संस्कृति। आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज का परिवर्तन तो किया, लेकिन लोगों के चिंतन जगत में, संस्कृति में हम परिवर्तन नहीं ला पाये। मन, चिंतन प्रक्रिया, चाहत, इच्छा, आकांक्षा, संस्कृति यदि समाज की प्रगति के परिपूरक न हो, तो क्रांति कैसे होगी? यह सब कुछ समाज के विकास में सहायक होना चाहिए।

कुछ भी करने में मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मन ही तो उसे संचालित करता है। मन यदि विज्ञान के आधार पर निर्मित न हो, उच्च संस्कृति के आधार पर निर्मित न हो, तो जो भी परिवर्तन क्यों न किया जाय, तो पुरानी संस्कृति ही रह जायेगी। इसलिए संस्कृति में, मन में परिवर्तन लाना होगा। इसी वजह से चीन में पतन हुआ, सोवियत रूस में पतन हुआ। उन्हें सांस्कृतिक स्तर में जो परिवर्तन लाना चाहिए था, वह वे नहीं ला पाये। कॉमरेड शिवदास घोष ने बहुत अर्सा पहले ही इस बात को उठाया था। आज स्थापना दिवस के मौके पर मैं कहूंगा कि आप लोग पार्टी के साथ काफी दिनों से हैं। पार्टी एक संस्कृति है, एक जीवन है। मन, मानसिकता ही मूल है। बाकी सब स्ट्रक्चर है। इसलिए संस्कृति में बदलाव लाने की जरूरत है, कम्युनिस्ट बनने की जरूरत है, कम्युनिस्ट संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। कम्युनिस्ट संस्कृति क्या है? कम्युनिस्ट संस्कृति के बारे में मार्क्स ने एक बार कहा था कि व्यक्ति सम्पत्ति से मुक्त मानवतावाद -जो बुर्जुआ लोग लाये थे- ही कम्युनिज्म है। कॉमरेड शिवदास घोष ने इसको और साफ करते हुए कहा कि निजी सम्पत्ति और निजी सम्पत्तिजनित मानसिकता, मानसिक ढांचा (minus private property mental complex) यानी मेरी सम्पत्ति, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा परिवार इत्यादि-ये जो 'मैं' को केन्द्र में कर दिया -इससे मुक्त मानवतावाद ही कम्युनिज्म है।

सामूहिक कल्याण, सामूहिक विकास के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास होगा। आज हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से जिन्दा रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रह नहीं पा रहा है। सामूहिक संघर्ष के जरिये समाज का परिवर्तन करने से ही सबका विकास हो सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है, आपके बच्चों को मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो आपके बच्चे भी गरीब किसान ही रह जायेंगे, गरीब मजदूर ही रह जायेंगे। जिस बच्चे को आपने पैदा किया, इस दुनिया में लाये, उसे आप इसी बदतर और गंदे समाज में छोड़कर चले जायेंगे जहाँ शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, जहाँ मनुष्यता नहीं है। इस समाज को आप छोड़िए, इसे बदल डालिए। यह बात सही है कि सर्वहारा दृष्टिकोण की बिक्री हो रही है। पार्टी के नाम पर चंदा भी हो रहा है। लेकिन वह नहीं हो रहा है, जिसे हम बार-बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का काम मतलब जुलूस निकालना, पोस्टर चिपकाना, अखबार बेचना, चंदा इकट्ठा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पार्टी स्थापना दिवस पर जगह-जगह की गई जनसभाएं

जयपुर : 26 अप्रैल को लाखेरी (राजस्थान) में कॉमरेड आर. पी. चौधरी की अध्यक्षता में एसयूसीआई(सी) का 67वां पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया। सभा की शुरूआत कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत से हुई। ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महिलाओं की सहभागिता पुरुषों से भी अधिक रही। लोग संसदीय पार्टियों को कोस रहे थे। मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं हरियाणा राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड सत्यवान ने सरल भाषा में भारत की एकमात्र क्रांन्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(सी) के बारे में विस्तार से बताया। सभी लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना। कार्यक्रम का संचालन राजू शर्मा ने किया। सभा का समापन अन्तर्राष्ट्रीय गान के साथ हुआ।

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.): भारत की एकमात्र सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी की जिला कमेटी जौनपुर के आह्वान पर 24 अप्रैल को बदलापुर में रैली एवं सभा का आयोजन किया गया। रैली पुरानी बाजार बाग से चलकर इन्दिरा चौक होते हुए डाक बंग्ला स्थित बाग में पहुँची जहाँ पर इस युग के अन्यतम महान मार्क्सवादी चिन्तक, दार्शनिक, पथ-प्रदर्शक, शिक्षक व सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके ऊपर रचित गीत गाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉ. रामआसरे मौर्य व संचालन कॉ. रविशंकर मौर्य ने किया। सभा को उप्र. भूमि अधिग्रहण-विरोधी मोर्चा के जौनपुर जिला अध्यक्ष पारसनाथ सिंह (पूर्व प्रधानाचार्य) ने भी सम्बोधित किया। रैली व सभा के दौरान प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहीं, तेज हवा व बरसात होती रही।

लखनऊ (उ.प्र.) : सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर आफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के 67वें स्थापना दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर जन-जीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ 28 अप्रैल को पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य समिति द्वारा एक राज्य स्तरीय जनसभा लखनऊ शहर के अमीनाबाद इलाके में स्थित गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल हाल में आयोजित की गयी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिव कॉ. वी.एन. सिंह ने की। मुख्य वक्ता के रूप में सभा को सम्बोधित

लखनऊ : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. रबिन समाजपति

करते हुए पार्टी की झारखण्ड राज्य समिति के सचिव कॉ. रबिन समाजपति ने केन्द्र व राज्य सरकारों की पूँजीपतिपरस्त जनविरोधी नीतियों की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से सुनहरे सपने दिखाकर तमाम रंगों की सरकारें आईं, सभी की नीतियाँ वही रहीं, केवल नारे बदलते रहे और वे सत्तासीन होकर पूँजीपतियों की सेवादास ही बनकर रह गयीं। यह क्रम बरकरार है। उन पार्टियों से आशा करना एक छलावे से अधिक और कुछ भी नहीं है। ज़रूरत है इन तमाम समस्याओं के खिलाफ लगातार जनान्दोलन

बदलापुर में रैली करते हुए एसयूसीआई(सी) के कार्यकर्ता

लाखेरी : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

का सैलाब खड़ा करके अन्ततः क्रांति के द्वारा इस शोषण-उत्पीड़न की चक्की में पीसने वाली पूँजीवादी व्यवस्था को ही ध्वस्त करने की और इस तरह से समाजवादी व्यवस्था कायम करके एक बेहतर समाज के संरचना की। कॉ. समाजपति ने अपनी व्यापक चर्चा के दौरान बहुत ही सूक्ष्म ढंग से यह दर्शाया कि हमारे देश में एस.यू.सी.आई.(सी) ही एकमात्र सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी क्यों है।

पार्टी की राज्य समिति के कार्यालय सचिव कॉ. जगन्नाथ वर्मा ने कहा कि पूँजीपतियों को टैक्स में छूट तथा उदारतापूर्वक अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर, सब्सिडी घटाकर उनके जीवन में अनिश्चितता का भय लगातार बढ़ाया जा रहा है। मजदूर हितैषी कानूनों को एक-एक कर खत्म कर पूँजीपतिपरस्त कानूनों को पारित व जबरन लागू करवाया जा रहा है। लोकतंत्र हितैषी होने का ढोंग रचने वाली केन्द्र में भाजपा-नीत सरकार संसद को दरकिनार करके अध्यादेश पर अध्यादेश लाती जा रही है। उन्हीं में एक और काला कानून - भूअधिग्रहण अध्यादेश लाया गया है जो ब्रिटिश काल के कानून से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कॉ. वर्मा ने कहा कि 'मेक इन इण्डिया' का सब्जबाग दिखाने वाली मोदी सरकार किसानों से जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देने पर आमादा है। किसानों की बिना सहमति के जबरिया उनसे जमीन छीनकर पूँजीपतियों को देने के लिए संसद को नजरंदाज कर यह अध्यादेश लाया जा रहा है। पार्टी के राज्य समिति सदस्य कॉमरेड एस. के. मालवीय ने कहा कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ज़रूरतों के निजीकरण ने आम-जन को बेहाल कर रखा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। देश की सरकार व तथाकथित बुद्धिजीवी भी ग़रीबों-मज़दूरों को मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म करने की वकालत कर रहे हैं, जो वैसे भी बहुत ही मामूली है। लेकिन लाखों हजार रुपये प्रति वर्ष उद्योगपतियों को विभिन्न बहानों से सौगात में दिये जा रहे हैं, उसकी चर्चा न मीडिया कर रहा है और न ही सरकारों को शर्म आ रही है। पार्टी के राज्य सचिव मण्डल सदस्य कॉ. पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा ने कहा कि नई सरकार आने के बाद से पाठ्यक्रमों में फासीवादी बदलाव किया जा रहा है। इतिहास को साम्प्रदायिक नजरिये से पेश करने के लिए तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। निर्लज्जता के साथ विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा किया जा रहा है और आये दिन ज़रूरी सवालों से ध्यान भटकाने के लिए दंगे कराये जा रहे हैं। इन फासीवादी शक्तियों के खिलाफ उन्नत विचारधारा के साथ संगठित प्रतिरोध के द्वारा ही किया जा सकता है।

दुर्ग (छ.ग.) : 67वें पार्टी स्थापना दिवस पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) दुर्ग, छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 28 अप्रैल को सभा की गई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के ओडिशा राज्य सचिव कॉ. धुर्जटी दास ने कहा कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश की आम मेहनतकश जनता महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, ईलाज न मिलने से होने वाली मौतों, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, महिलाओं व बच्चियों पर होने वाले अपराध आदि समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने जनजीवन की इन ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ संगठित होकर जोरदार जनआन्दोलन गठित करने का आह्वान किया। इस जनआन्दोलन को विकसित करते-करते जनता इन तमाम समस्याओं की जननी इस शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को क्रान्ति के जरिये उखाड़ फेंकेगी और उत्पादन के तमाम साधनों पर सामाजिक मालिकाना कायम करना होगा। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रख कर सर्वहारा के महान क्रान्तिकारी नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने 24 अप्रैल 1948 को देश की एकमात्र सही क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की स्थापना की थी। उन्होंने इस दिन आन्दोलन को तेज करने की शपथ लेने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।

बुढ़लाडा (पंजाब) : 67वें पार्टी स्थापना दिवस पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पंजाब सांगठनिक कमेटी की ओर से 3 मई को वर्कर्स यूनियन हाल में एक जनसभा की गई। पार्टी की मध्यप्रदेश सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड प्रताप सामल सभा के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने कहा कि मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया और बीजेपी सरकार को तो सत्ता में आये अभी महज 6 महीने ही हुए हैं लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मोदीजी के काम के विश्लेषण का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने इस थोड़े से समय में ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विनाश का एक रिकार्ड कायम कर दिया है। निजीकरण, व्यापारीकरण और

बुढ़लाडा : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. प्रताप सामल

साम्प्रदायीकरण से मेहनतकशों के हर तबके के लोग प्रभावित हैं। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के पंजाब राज्य संयोजक कॉमरेड अमीन्दरपाल सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर पार्टी द्वारा लिया गया स्टैण्ड समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ऑल इण्डिया डीएसओ, दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. भास्कर ने पार्टी के निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सही कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताया। कॉ. इन्द्रजीत जोधा ने मंच का संचालन किया।

फासीवादी शक्तियों पर सोवियत रूस की लाल सेना की विजय की 70वीं सालगिरह पर झारखंड में विचार गोष्ठी

'फासीवाद का खतरा और उसका समाधान किस रास्ते' विषय पर विचार गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कॉ. रबिन समाजपति

कॉ. रंजीत धर का भाषण..

(पृष्ठ 4 का शेष)

करना ही रह गया है। कार्यक्रम नहीं रहा, तो घर में बैठे हुए हैं। आज जुलूस निकलेगा चलो, आज मीटिंग होगी चलो। लेकिन जनता के साथ रहना, जनता को सचेत करना, जनता के साथ संपर्क बनाना नहीं हो रहा है। हम जहाँ रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, मुहल्ले में रह रहे हैं, वहां सभी लोगों के साथ, सभी परिवारों से संपर्क करना चाहिए। उनके सुख-दुख, उनके जीवन को हमें जानना चाहिए। सबके साथ, जनता के साथ एक आत्मीय रिश्ता कायम करना चाहिए। यह रिश्ता ऐसा हो कि आस-पास के लोग आपके पास आयें, आपसे अपने मन की बात कहें, अपनी समस्याओं-परेशानियों को बतायें जिससे उनके मन को शांति मिल सके। हम और कुछ कर पायें या नहीं, उनकी बातों को सुन तो सकते हैं, उनके सुख-दुख में शामिल तो हो सकते हैं। हम जनता के बीच नहीं रहते हैं, हमारा mass life नहीं है। हम कार्यक्रम के आधार पर जनता के बीच जाते हैं। हमें हर घर में जाना चाहिए, हर घर-परिवार के साथ परिचित होना चाहिए, हर घर अपना घर होना चाहिए। हमें जनता के बीच रहकर, उनके सुख-दुख में शामिल होकर उनके अंदर परिवर्तन लाना होगा। ऐसा न करने से आप समाज में क्रांति की मानसिकता तैयार नहीं कर पायेंगे। हम भाषण देते हैं, अखबार बेचते हैं, इससे नहीं होगा।

आप जानते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद क्या सब हो रहा है। भाजपा काफी खतरनाक है। खतरनाक इस मायने में कि भाजपा देश को आधुनिक विज्ञान की बजाय ऋषि-मुनियों के जमाने में ले जाना चाहती है। वह स्कूली पाठ्यक्रम में, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद आदि ला रही है, जो कि आज पुराना पड़ गया है, Obsolete हो गया है। गीता पढ़ाने की बात हो रही है। हिन्दुत्व को लाया जा रहा है। एकमात्र हिन्दू ही भारत में रहेंगे और हिन्दुत्व के आधार पर चलना होगा। ये पुराने विचार, प्रतिक्रियावादी विचार समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं।

उद्योगों में नई-नई मशीनें लाकर मजदूरों की छंटनी की जा रही है। एक समय टाटा के उद्योग में लगभग 70-80 हजार लोग काम करते थे। लेकिन आज टाटा के उद्योग में मात्र 16-17 हजार लोग काम करते हैं। नई-नई मशीनों के जरिये वे और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। एक तरफ वे उत्पादन के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिंतन के लिए ईश्वर की बात करते हैं, धर्म, वेद, गीता की बात करते हैं। उत्पादन में, मुनाफा कमाने में उन्हें विज्ञान की जरूरत है। मजदूरों की छंटनी के लिए, किसानों की फसल का उचित मूल्य न देने के लिए उन्हें विज्ञान की जरूरत है। लेकिन चिंतन प्रक्रिया के लिए उन्हें ईश्वर चाहिए। पुराना युग चला गया। रामायण-महाभारत का युग फिर नहीं आयेगा, ऋषि-मुनियों का युग नहीं आयेगा। विज्ञान और सभ्यता धीरे-धीरे बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनके अनुसार समाज में गरीबी का मूल कारण है भाग्य, ईश्वर। उनका कहना है ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर की प्रार्थना करो। यदि ईश्वर को संतुष्ट कर सको, तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन उत्पादन के मामले में ईश्वर नहीं। यह उनका अंदरूनी द्वन्द्व है। उनका मानना है कि पिछले जन्म में आपने पाप किया था, अन्याय किया था, इसलिए इस जन्म में आपकी यह हालत है। इस जन्म में अगर आप ईश्वर को संतुष्ट कर सकेंगे, तो अगले जन्म में आपकी यह समस्या नहीं रहेगी। आपकी मुक्ति का उपाय ईश्वर है। यानी जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं, उस वजह पर से वे आपका ध्यान हटा रहे हैं। वे विज्ञान से आपका ध्यान हटा रहे हैं, तर्क से आपका ध्यान हटा रहे हैं।

साम्प्रदायिकता, भेदभाव की समस्या भी आपके सामने है। भारत में मुगल आये, हूण आये, अंग्रेज आये। अंग्रेजों ने काफी दिनों तक देश पर राज किया। बाहर से अनेक लोग आये, अनेक हमले हुए। बाहर से संकर जाति यानी एंग्लो इंडियन आये। यहाँ हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं –कितनी जाति-धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। आजादी आंदोलन में अपनी मुक्ति के लिए हिन्दू-मुसलमान सभी एक साथ मिलकर लड़े। लेकिन भाजपा ने आकर धर्म के नाम पर जनता में विभेद पैदा कर दिया। जनता के अंदर पुरानी धारणाओं, अप्रचलित धारणाओं–जिनका रोजमर्रा के जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है–उनको फैलाना शुरू किया। उसने कहना शुरू किया कि धर्म पर विश्वास करो, वास्तविक स्थिति का विचार मत करो। भाजपा ने यह सर्वनाश किया।

भारत में आज आप देखेंगे कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी एक समरूप पार्टी नहीं है। इसके अंदर भी अलग-अगल गुट हैं। नरेन्द्र मोदी बहुत ताकतवर प्रशासक हैं। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के मुख्य सचिवों की नियुक्ति खुद की और वे उनसे सीधे संपर्क में रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। वे एक तानाशाह हैं, फासिस्ट हैं। एक समय मोदी के खिलाफ पूरे देश मे इतनी नफरत पैदा हो गयी थी कि वाजपेयी भी उनके साथ एक मंच पर भाषण देने को तैयार नहीं थे। जो नरेन्द्र मोदी देश की आम जनता के लिए सबसे घृणित व्यक्ति थे, उन्हीं मोदी को पूंजीपति वर्ग ने करोड़ों रुपये खर्च कर, प्रचार कर पिछले चुनाव में सत्तासीन किया।

दरअसल चुनाव तो एक छलावा बन गया है। पैसे, शराब और गुंडागर्दी के जरिये चुनाव होता है। चुनाव में घर-घर में पैसे आ जाते हैं, नौजवानों को शराब मिलती है, गरीबों की इज्जत खरीद ली जाती है। लेकिन सालों साल आम लोगों को भूखों रखा जाता है। एक-एक पार्टी करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च करती है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या उनमें से किसी ने अपनी सम्पत्ति बेची, अपनी जमीन-जायदाद बेची? तो पैसे कहाँ से आते हैं? कौन देते हैं? चुनाव के दौरान उम्मीदवार इतने पैसे खर्च करते हैं, लगता है नोटों की बारिश हो रही है। दरअसल पैसे देते हैं पूंजीपति। चुनाव में वे अपने एजेंट खड़ा करते हैं। जीतकर वे पूंजीपतियों का ही स्वार्थ देखते हैं। मानिए दस करोड़ रुपये खर्च कर एक एमपी को जीताया गया। जीतने के बाद वह बीस करोड़ रुपये देता है। आज यह बात आम हो गयी है। आज चुनाव रह ही नहीं गया है। वह एक छलावा के सिवा कुछ नहीं है।

यहाँ प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस-मिलिट्री इन सब में फासीवाद आ चुका है। फासीवाद में प्रशासनिक ताकत को केन्द्रीभूत किया जाता है। जनता के हाथ में जो भी जनवादी अधिकार थे, उन सभी को छीन लिया गया है। पूरी सत्ता को राज्य के हाथों में केन्द्रीभूत किया जा रहा है। यही फासीवाद है। हमारे देश में प्रशासनिक फासीवाद बहुत दिन पहले ही कायम हो चुका है। यहाँ कानून पैसों में बिकता है। विचार पैसों में बिकता है। चुनाव पैसों से होता है। यहाँ संसद है पर कोई जनतंत्र नहीं है।

मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद–ये सभी जनता दल में थे, जयप्रकाश नारायण के समय एक साथ थे। बाद में मुलायम सिंह ने यूपी में समाजवादी पार्टी बनायी, बिहार में लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल तथा नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाया। हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ मुलायम को अध्यक्ष मानकर ये सभी पार्टियाँ एक मंच पर आ रही हैं, एक ही पार्टी बनने वाली है। भाजपा के खिलाफ खुद सत्ता में आने के लिए ये लोग ऐसा करने जा रहे हैं।

राहुल के माध्यम से कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। मनमोहन सिंह को वे नहीं ला पाये। क्योंकि मनमोहन सिंह में शासन चलाने की वैसी क्षमता नहीं है। मनमोहन सिंह के पीछे से सोनिया ही शासन चलाती थी। मनमोहन सिंह एक मशीन हैं। उनकी अपनी पर्सनलिटी नहीं है। इसलिए वे राहुल को लेकर कोशिश कर रहे हैं। होगा कि नहीं कहना मुश्किल है। वे प्रियंका को भी लाने की कोशिश में हैं।

पूरे देश में फासीवाद लाने के लिए भाजपा के माध्यम से कोशिश हो रही है। भारत विशाल देश है। यह अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, बांग्लादेश जैसा कोई छोटा-सा देश नहीं है। यहाँ तमिल हैं, तेलगु हैं, मलयाली हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, हरियाणवी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पंजाबी हैं। यहाँ अनेक प्रांत हैं, प्रांतीय मानसिकता है, प्रांतीय आचार-विचार हैं। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी– ये सभी क्षेत्रीय पूंजी के प्रतिनिधि हैं। इनकी पार्टियाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। तेलगु देशम, शिव सेना –ये भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। ये अखिल भारतीय पार्टियाँ नहीं हैं। यहाँ क्षेत्रीय पूंजी के साथ एकाधिकारी पूंजी का द्वन्द्व है। क्षेत्रीय पूंजी के साथ क्षेत्रीय पूंजी का द्वन्द्व है। भारत में एकाधिकार पूंजी के साथ क्षेत्रीय पूंजी का, बड़ी पूंजी के साथ छोटी पूंजी का द्वन्द्व है, विरोध है। इस कारण से यहाँ पूर्णरूपेण फासीवाद (Allout Fascism) का आना मुश्किल है। इस बात को बहुत समय पहले ही कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था।

नरेन्द्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने वही किया, जो पूंजीपति चाहते थे। हमारे देश के पूंजीपति वर्ग ने आजादी के बाद देश के पूरे बाजार का शोषण कर काफी मुनाफा कमाया। इस पूंजी को यहाँ निवेश करना और उससे मुनाफा कमाना अब संभव नहीं है। इसलिए इस पूंजी को बाहर ले जाने की जरूरत है और उन्हें बाहर का बाजार तब मिलेगा, जब बाहर की पूंजी को यहाँ आने दिया जायेगा। अलग-अलग देश की अलग-अलग सीमा है, अलग-अलग बाजार है। फ्रांस का बाजार है, ब्रिटेन का बाजार है, जर्मनी का बाजार है, सऊदी अरब का बाजार है, श्रीलंका का बाजार है। हम यदि उन बाजारों में जाकर उद्योग तैयार कर सस्ते दर पर मजदूरों से श्रम लेकर तथा वहाँ की प्राकृतिक सम्पदा को लूटकर मुनाफा कमायेंगे तो वे हमें वहाँ क्यों घुसने देंगे? तो दूसरे देश में हमारे देश की पूंजी कैसे जायेगी? इसलिए वे कह रहे हैं कि भारत में विदेशी पूंजी आने दो। भारत में विदेशी पूंजी आयेगी और यहाँ की पूंजी बाहर जायेगी। इसलिए विदेशी पूंजी को हमारे देश में लाने के लिए दबाव आ रहा है। इसी कारण से नरेन्द्र मोदी को लाया गया। नरेन्द्र मोदी ने बैंक में, बीमा में विदेशी पूंजी की घुसपैठ आसान बना दी। प्रतिरक्षा क्षेत्र मे भी विदेशी पूंजी की अनुमति दे दी गयी है। विदेशी पूंजी को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने, लूटने का रास्ता खोल दिया गया है।

पूंजीवाद में संकट बढ़ता ही रहेगा। आज प्रति दिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मजदूर आत्म हत्याएं कर रहे हैं। निर्भया कांड के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लोगों में असंतोष और विक्षोभ बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने की क्षमता न भाजपा में है, न किसी दूसरी पार्टी में है। इसलिए शासक वर्ग लोगों की संस्कृति पर चोट कर रहा है ताकि लोग आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ते हुए राजसत्ता पर कब्जा न कर लें। आज टीवी और अखबारों में विज्ञापनों में महिलाओं की नग्न तस्वीरें दिखायी जाती हैं। मालिक लोग, पूंजीपति लोग महिलाओं के जिस्म को बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। गंदी संस्कृति की बाढ़ लाकर वे लोगों के चरित्र को गिराना चाहते हैं। लोग एकजुट होकर अन्याय-जुल्म के खिलाफ लड़े नहीं, इसलिए उनकी नैतिक रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। तभी तो शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। यहाँ तक कि पान की दुकान में भी, दवा की दुकान में भी आज शराब उपलब्ध है। टीवी में, सिनेमा में सिर्फ सेक्स और वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं है। पूंजीपति वर्ग जानता है कि यदि लोगों की संस्कृति में गिरावट ला दी जाय, तो उनका लूट का राज चलता रहेगा। यह बात हम कॉमरेड शिवदास घोष की सीख के आधार पर कह रहे हैं। यह महान विचार हमारे पास है। लेकिन हम लोग लाचार होकर बैठे हुए हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, समझ बुझकर भी हम नहीं कर रहे हैं। आज एसयूसीआई(सी) स्थापना दिवस के मौके पर हमें ऐसा करने का संकल्प लेना चाहिए।

आज हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं। हम अपनी कमजोरियों के कारण संभावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नीति हमारे पास है, कॉमरेड शिवदास घोष की सीखें हमारे पास हैं, उनका जीवन-संघर्ष हमारे सामने है, उनका चरित्र हमारे पास है। हमें इस नीति पर खरा उतरना होगा। देश में संकट घनीभूत हो रहा है। आदमी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई सीमा नहीं है। जनता के अंदर काफी विक्षोभ है। अन्याय हो रहा है, हमले हो रहे हैं। लेकिन रोकेगा कौन? आज इसे रोकने की जिम्मेवारी कॉमरेड शिवदास घोष ने हमारे कंधों पर सौंपी है। इस जिम्मेवारी को हमें पूरा करना है। 24 अप्रैल के दिन हमें यही संकल्प लेना है। कॉमरेड शिवदास घोष हमें जो रास्ता दिखाकर गये हैं, जो विचार छोड़कर गये हैं, उसका विरोध कर सके ऐसी कोई ताकत दुनिया में नहीं है। हमें उनके चरित्र को अपनाने की जरूरत है। हम इस काम में पीछे पड़ गये हैं।

देश क्रांति चाहता है, दुनिया क्रांति चाहती है। लोग क्रांति का इंतजार कर रहे हैं। जो चरित्र, जो शक्ति हमारे पास है, उसे इस्तेमाल करने लायक जो साहस हममें होना चाहिए, जो मानसिकता होनी चाहिए, हममें उसकी कमी है। जीवन में चरित्र चाहिए, संस्कृति चाहिए। आज जिस परिस्थिति के सम्मुख हम खड़े हैं, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके इसे बदल डालें। यदि हम चाहें तो हम अपने जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। कॉमरेड शिवदास घोष ने हमें यही रास्ता दिया है। यही हमारे लिए 24 अप्रैल की सीख है।

इंकलाब जिन्दाबाद!

एसयूसीआई (सी) जिन्दाबाद!

कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम!

योजना के बजट में कटौती के खिलाफ यूपी में सड़कों पर उतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां

मैनपुरी में आगंनवाड़ी कर्मियों के विशाल सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए एआईयूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉ. अचिंत्य सिंहा

ए.आई.यू.टी.यू.सी. से सम्बद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन, उ.प्र. के आह्वान पर 11 मई को उ.प्र. राज्यव्यापी आन्दोलन के क्रम में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए और केन्द्र सरकार व उ.प्र. सरकार को ज्ञापन भेजे गए। समेकित बाल विकास योजना(आईसीडीएस) के बजट में भारी कटौती, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना को बन्द करने की सिफारिश, योजना में प्राइवेट ठेकेदारों/एनजीओ/दलालों को खुली छूट देने तथा एसोसिएशन के सात सूत्री लम्बित मांगपत्र पर ध्यान न दिये जाने के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं सड़कों पर उतरी। उनकी सात सूत्री मांगों में योजना के विस्तार, नई भर्ती करने, आंगनबाड़ी कर्मियों के नियमितीकरण, निजीकरण बंद करने, पंचायतों/एनजीओ का हस्तक्षेप बंद करने की मांगें शामिल थी।

रामपुर तथा मेनपुरी जनपदों में तो रिकार्ड तोड़ भीड़ जुटी और 1000 से भी अधिक आंगनबाड़ी कर्मियों ने कई घण्टे पूरे शहर को जाम रखा।

मेनपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन का जनपदीय सम्मेलन रविवार को कलक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न जिलों से भी आंगनबाड़ी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कार्यकर्त्रियों ने केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा योजना बंद करने का बयान देने की घोर निन्दा की गई। कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन राज्यमंत्री आलोक शाक्य को सौंपा।

जिलाध्यक्ष सरिता शाक्य के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिकाएं कलक्ट्रैट पर एकत्रित हुई जहाँ से सम्मेलन स्थल तिकोनिया पार्क तक जुलूस निकाला गयाा। सम्मेलन में एआईयूटीयूसी के सचिवमंडल सदस्य एवं जेपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अचिन्त्य सिन्हा ने आईसीडीएस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा खत्म करने की साजिश पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आईसीडीएस योजना का लाभ न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को ही है बल्कि देश के कुपोषित बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं को भी मिल रहा है। आईसीडीएस योजना बंद करना देश की विशाल संख्या के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं से एक विशाल आन्दोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। आंगनबाड़ी इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमारी ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। कॉ. राजबली ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। राज्यमंत्री आलोक शाक्य व पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष दीप सिंह पाल ने उनकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कानपुर, जिलाध्यक्ष हीरावती, रामपुर की अध्यक्ष सोमवती शर्मा, आगरा से श्रीमती वर्मा, विमलेश चौहान, मुरादाबाद मण्डल अध्यक्ष सोमवती शर्मा आदि पदाधिकारी मौजूद थी।

बरेली में आन्दोलन का नेतृत्व आंगनवाड़ी एम्पलाइज फैडरेशन ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चाहल ने किया। झण्डे-बैनरों से सुसज्जित जुलूस बरेली जंक्शन से जिला अधिकारी कार्यालय पहुँच कर सभा में बदल गया। आंगनबाड़ी नेताओं ने कहा कि "अच्छे दिनों" का सपना दिखाकर आई मोदी सरकार देश के आईसीडीएस योजना की 20 करोड़ से अधिक लाभार्थियों व 25 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों के पेट पर लात मार रही है। योजना के बजट में 56% की कटौती की गई है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों का आह्वान किया कि इसके खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित किया जाए।

मुरादाबाद में आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए एसोसियेशन की प्रदेश महासचिव शशिबाला ने कहा कि उ.प्र. सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों पर काम का भारी बोझ लाद रही है तथा पिछले 13 वर्ष से मानदेय में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की है। सरकार ने इस बीच बहुत धृष्टता से अपने मंत्रियों/विधायकों के वेतन भत्तों में कई बार भारी बढ़ोतरी की थी। उन्होंने इस पर रोष प्रकट करते हुए आन्दोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। अमरोहा में सत्यबाला चौधरी, हापुड़ में सुरभि शर्मा, सहारनपुर में संगीता यादव आदि ने आन्दोलन का नेतृत्व किया।

मिड डे मील का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपने की योजना के विरोध में

हरियाणा में मिड-डे मील कर्मियों का गुस्सा फूटा

रिवाड़ी (हरियाणा) : मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन सम्बन्धित ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. ने अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए 8 मई को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। इसमें सैकड़ों मिड डे मील वर्कर्स ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व यूनियन की महासचिव ओमवती, प्रधान सुरस्ती ने किया। यूनियन नेताओं ने कहा कि प्राइवेट कम्पनी अपने मुनाफे के लिए घटिया सामग्री वितरित करेगी जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे। मिड डे मील कार्यकर्ता गरीब परिवारों से है, परन्तु उनको गुजारेलायक की तो बात दूर रही सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। यूनियन की मांग है कि 15000रु प्रतिमाह मेहनताना दिया जाए, गर्मी-सर्दी की ड्रेस दी जाए, छुट्टियों का मेहनताना भी दिया जाए और स्कूलों में मिड डे मील वर्कर्स की हाजिरी लगाई जाए।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए यूनियन के प्रान्तीय सलाहकार कॉमरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि भाजपा की सरकार में मिड-डे-मील वर्कर्स भी अच्छे दिनों के इन्तजार में हैं। चुनावों में स्कीम वर्कर्स के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गई थीं। परन्तु अब तक उनकी रोजी-रोटी छीनने पर उतारू है। कृषक खेत मजदूर संगठन के नेता कॉ. रामकुमार, ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. के जिला सचिव कॉमरेड बलराम ने भी सम्बोधित किया।

महेन्द्रगढ़, हरियाणा: शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपने की योजना के विरोध में मिड-डे मील एवं स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता 26 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षामंत्री के महेन्द्रगढ़ आवास पर पहुँची। शिक्षामंत्री की अनुपस्थिति में अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षकों पर मिड डे मील से अध्यापकों का काम प्रभावित होता है। यह केवल झूठा बहाना है। इस बहाने में हजारों महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा। पढ़ाई चौपट होने के कई और कारण हैं जिनकी तरफ से सरकार आंखें मूंदे हुए है। 8वीं कक्षा तक पास-फेल नीति लागू न करना, ग्रेडिंग व सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, समय पर पाठ्यपुस्तकें न भेजना, साल भर अध्यापकों के खाली पड़े पद न भरना, जनगणना, वोट बनाने, चुनाव आदि गैर शिक्षण कार्यों में अध्यापकों की ड्यूटि लगाना इनमें प्रमुख हैं। प्रदर्शन में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव मास्टर सूबेसिंह, मिड डे मील एवं स्वयं सहायता समूह की जिला प्रधान उर्मिला, एआईयूटीयूसी के कॉमरेड सुभाष, संतोष, बाला, इन्दिरा, कविता, रामरती, कौशल्या, पूनम, सुमित्रा, शकुन्तला, मीरा, सोनिया सहित सैकड़ों मिड डे मील कार्यकर्ताओं एवं यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7-8 and 22-23 Fortnightly, Date of Printing : 20 May, 2015

संयुक्त आंदोलन गठित करने की दिशा में आगे आएं

आइसा के राष्ट्रीय सम्मेलन में आमन्त्रित ए.आई.डी.एस.ओ. के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा की अपील

दिल्ली में आइसा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड अशोक मिश्रा

दिल्ली : 10-11 मई को नई दिल्ली में आइसा का 8वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ए. आई.डी.एस.ओ. के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा आमंत्रित थे। कॉमरेड अशोक मिश्रा ने सम्मेलन के खुले अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आज समस्या न केवल शिक्षा पर पूंजीवादी-साम्राज्यवादी हमले का है बल्कि आज समस्या पूरे मानवता पर हमले की हो चुकी है। यह एक बहुत ही बुरा दौर चल रहा है जब देश में फासीवादी ताकतें तेजी से सर उठा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर यह वक्त बहुत ही आशाजनक तस्वीर भी पेश कर रहा है जब देश के तमाम जनवादपसंद लोग और ताकतें एक संयुक्त जनवादी आंदोलन की जरूरत को गहराई से महसूस कर रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन की जरूरत को महसूस करते हुए ही पूरे देश भर में आंदोलन की लहरें उठ रही हैं। संगठित हों या असंगठित, आंदोलन उठ रहे हैं। दिल्ली में दामिनी के साथ हुए वीभत्स बलात्कार की घटना के बाद हुए आंदोलन और अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों का संयुक्त आंदोलन इसकी साफ गवाही है। आज समय की मांग है कि इन आंदोलनों को एक सही दिशा में संचालित किया जाए। यह जिम्मेदारी हम पर है। वैचारिक मतभेदों के बावजूद आज वक्त की जरूरत है कि हम एक साझा कार्यक्रम बनाकर पूरे देश भर में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाप्रेमी जनता के साथ मिलकर शिक्षा और मानवता पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक जुझारू संयुक्त आंदोलन का निर्माण करें। यदि हम ऐसा करने में विफल रहे तो अवश्यंभावी रूप से फासीवादी ताकतों की जड़ें मजबूत होंगी जो पूरे मानव समाज के लिए भयंकर खतरा साबित होगा।

उन्होंने तमाम छात्र संगठनों से अपील की कि वे समय की इस जरूरत को समझते हुए संयुक्त आंदोलन के निर्माण की दिशा में आगे आएं।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ झारखण्ड बंद सफल

जमशेदपुर : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ में सड़कों पर उतरे एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

जमशेदपुर : केन्द्र सरकार के किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 4 मई को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट), सीपीआई, सीपीएम, जेवीएम, राजद और जदयु आदि पार्टियों ने मिलकर झारखण्ड बंद कराया। यह बंद झारखण्ड के लगभग सभी जिलों में सफल रहा। राँची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद व गढ़वा में बंद के दौरान एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। कुल मिलाकर यह बंद पूर्ण रूप से शान्तिपूर्ण रहा।

मोगा कांड के खिलाफ एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ताओं ने जताया रोष

बुढ़लाडा : मोगा कांड के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

बुढ़लाडा (पंजाब) : गत दिनों हुए मोगा में बस से लड़की को धकेल कर मारने की घटना के खिलाफ 10 मई को यहाँ एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर और नारे लगा कर रोष जताया। यह रोष प्रदर्शन बस स्टैण्ड से शुरू हुआ और पुरानी कचहरी, रेलवे रोड, गाँधी बाजार आदि से होते हुए कस्बे के कई बाजारों से गुजरा। इस मौके पर पार्टी के पंजाब सूबे के कन्वीनर कॉ. अमीन्दर पाल सिंह ग्रेवाल ने लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मोगा बस में घटी घटना बड़ी शर्मनाक घटना है। इसने पंजाब में औरतों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बादल परिवार से सम्बन्धित बस में घटी घटना से पता चलता है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। संदीप सिंह ने कहा कि जहाँ यह घटना अपने आप में शर्मनाक है, वहीं पंजाब के मंत्री का यह बयान कि यह तो रब की मर्जी थी, सरकार की महिलाओं के प्रति घटिया सोच को दर्शाता है। उन्होंने सरकार से माँग की कि मोगा कांड के दोषियों को सख्त सजा दी जाये, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और बस सेवाओं का निजीकरण बंद किया जाये।

इस मौके पर कॉ. इन्दरजीत सिंह जोधा, हरदीप कौर, सरसती, गुरदीप सिंह, परमिन्दर सिंह, निर्मल सिंह, तरसेम सिंह समेत काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की।

झारखण्ड में राजनीति शिक्षण शिविर आयोजित

घाटशिला : एसयूसीआई(सी) झारखण्ड राज्य कमेटी की ओर से 3 से 5 अप्रैल तक तीन दिवसीय राजनीति शिक्षण शिविर लगाया गया। इसका संचालन पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रंजीत धर ने किया। शिविर में चर्चा के विषय थे जनवादी केन्द्रीयता, सीपीआई, सीपीएम व सीपीआई(एमएल) जैसी तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियों से एसयूसीआई(सी) की मूल राजनैतिक लाइन में फर्क, सर्वहारा संस्कृति, समाजवादी खेमे के पतन का कारण, देश-दुनिया में आज के कम्युनिस्टों के सामने भावी सम्भावनाएं। पार्टी के राज्य सचिव कॉ. रबीन समाजपति व अन्य राज्य कमेटी सदस्यों ने ग्रुप चर्चाओं का संचालन किया।

घाटशिला में शिक्षण शिविर को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड रंजीत धर

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631